दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित तिथि: 30 जनवरी 2024

निर्णय की तिथि: 13 फरवरी 2024

रि.या.(सि.)11649/2021

नितिन थॉमस .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विराज शंकर कदम, अधिवक्ता।

बनाम

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: प्रत्यर्थी-1 के लिए श्री टी. सिंहदेव, श्री अभिजीत चक्रवर्ती, सुश्री रमनप्रीत कौर, श्री भानू गुलाटी, सुश्री अनुम हुसैन, श्री आभास सुखरामानी और श्री तनिष्क श्रीवास्तव, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थी-2 के लिए श्री किर्तीमान सिंह, श्री वैज़ अली नूर, श्री वरुण राजावत, श्री कार्तिक बैजल, श्री वरुण प्रताप सिंह,

सुश्री श्रेया वी. मेहरा और सुश्री विधि जैन, अधिवक्ता।

कोरमः

माननीय श्री न्यायमूर्ति सी. हरी शंकर

निर्णय

13.02.2024

मुद्दा

1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (आईएमसी अधिनियम) की धारा 12 और 13(4ख) के तहत विरचित विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 2002 (तत्पश्चात एफएमआई विनियम) में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्रता की आवश्यकता के संदर्भ में याचिकाकर्ता को भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2014 को एक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था जिसमें यह प्रमाणित किया गया कि वह किसी स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु किसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश के लिए पात्र है, ताकि वह भारत में एमबीबीएस के समकक्ष प्राथमिक चिकित्सा अर्हता प्राप्त कर सके। उक्त पात्रता प्रमाण-पत्र एनएमसी द्वारा 26 जुलाई 2021 के एक पत्र द्वारा वापस ले लिया गया था जिसके आधार पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने 23 अगस्त 2021 के एक पत्र द्वारा जून 2020 में आयोजित विदेशी चिकित्सा स्नातक

परीक्षा (एफएमजीई) में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और याचिकाकर्ता को जारी 18 नवंबर 2020 का एफएमजीई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया था।

2. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, एनएमसी के 26 जुलाई 2021 और एनबीईएमएस के 23 अगस्त 2021 के पत्रों को अभिखंडित करने की मांग करता है। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने एनएमसी को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि वह दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) को एक अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए लिखे, जिससे याचिकाकर्ता को एक चिकित्सक के रूप में पंजीकृत किया जा सके जो दिल्ली में चिकित्सा अभ्यास करने के हकदार हो।

तथ्य

3. किसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में किसी भी स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने से पूर्व, एक छात्र को एफएमआई विनियमों के अनुसार एनएमसी (पहले एमसीआई) में आवेदन करने और पात्रता का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। विदेश में पाठ्यक्रम पूरा करने और प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान अहर्ता/एमबीबीएस प्राप्त करने के बाद, यदि छात्र भारत में चिकित्सक के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसे एफएमजीई उत्तीर्ण करना होगा, जिसे "जाँच परीक्षण" भी कहा जाता है।

<u>याचिकाकर्ता के बारहवीं कक्षा के एआईएसएससीई का परिणाम</u>

4. याचिकाकर्ता ने अपनी बारहवीं कक्षा की परीक्षा सेंट डोमिनिक सैवियो हाई स्कूल, पटना से उत्तीर्ण की जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध है। सीबीएसई द्वारा जारी अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाणन परीक्षा (एआईएसएससीई) अंक-पत्र पर परिलक्षित बारहवीं कक्षा में सीबीएसई द्वारा उन्हें दिए गए अंक और ग्रेड निम्नानुसार थे:

विषय कोड	**विषय**	**अंक प्राप्त हुए**				**स्थितीय स्नातक**
301	अंग्रेज़ी	092	XXX	बयानवे		A1
043	रसायन विज्ञान	023	029	बावन		D2
044	जीवविज्ञान	034	030	चौसठ		C2
049	चित्रकारी	025	059	चौरासी		B2
065	सूचना विज्ञान अभ्यास	040	029	उन्नहत्तर		C2
042	भौतिक विज्ञान	011	026	चालीस		E
500	कार्य अनुभव					B1

502	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा					B2
503	सामान्य अध्ययन					B1

5. यह नोट किया गया कि संक्षिप्त में "एफटी" का अर्थ "लिखित परीक्षा में फेल" है। हालांकि, प्रमाण-पत्र पर याचिकाकर्ता का समग्र परिणाम "पास" के रूप में दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, अंक-पत्र के पीछे निहित नोट्स/निर्देशों पर- जो याचिकाकर्ता द्वारा दायर नहीं किया गया है, परंतु प्रत्यर्थी 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री सिंहदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया था- यह विशेष रूप से नोट किया गया है कि ग्रेड 'ई' द्वारा ये संकेत किया गया है कि उम्मीदवार उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा था| ग्रेडिंग के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षा और उत्तीर्ण होने के मानदंड की योजना" से संबंधित सामान्य निर्देश खंड 38(v) में इस प्रकार प्रदान करते हैं:

> "(v) ग्रेड देने के लिए, बोर्ड सभी उत्तीर्ण छात्रों को छात्रों को रैंक क्रम में रखेगा और निम्नानुसार ग्रेड प्रदान किया जाएगा:
>
> ए-1 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से शीर्ष 1/8$^{वां}$
>
> ए-2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से अगला 1/8$^{वां}$
>
> बी-1 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से अगला 1/8$^{वां}$

बी-2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से अगला 1/8वां

सी-1 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से अगला 1/8वां

सी-2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से अगला 1/8वां

डी-1 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से अगला 1/8वां

डी-2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से अगला 1/8वां

ई असफल अभ्यर्थी"

6. इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता बारहवीं कक्षा में अपने भौतिक विज्ञान के परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा था|

<u>पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र</u>

7. 1 अगस्त 2012 को, याचिकाकर्ता ने रूस में स्टावरोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी (एसएसएमयू) से एमबीबीएस प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र देने के लिए एमसीआई को आवेदन किया। आवेदन पत्र में उसे दसवीं और बारहवीं कक्षाओं में विभिन्न विषयों में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण दर्ज करने की आवश्यकता थी, साथ ही यह भी कि वह उक्त विषयों में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हुआ था या नहीं। अपने बारहवीं कक्षा के प्रदर्शन के संबंध में, याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार विवरण दर्ज किया:-

विषय	**अधिकतम अंक**		**प्राप्त अंक**		**%परिणाम**
	थ्योरी	**प्रैक्टिकल**	**थ्योरी**	**प्रैक्टिकल**	**पास/फेल**

अंग्रेज़ी	100		92		92
भौतिक विज्ञान	70	30	23	29	52
रसायन विज्ञान	70	30	34	30	64
जीवविज्ञान	70	30	11	29	40
पीसीबी टोटल	210	90	68	88	52

8. पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन में दर्ज किए गए विवरणों की तुलना से दो विशेषताएं तुरंत स्पष्ट हो जाती हैं। पहला यह कि विभिन्न विषयों के विरुद्ध प्राप्त अंकों को पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया गया था, रसायन विज्ञान में प्राप्त अंकों को भौतिकी में प्राप्त किए गए अंकों के रूप में दिखाया गया था, जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों को रसायन विज्ञान में प्राप्त किए गए के रूप में दिखाया गया था और भौतिकी में प्राप्त अंकों को जीव विज्ञान में प्राप्त किए गए के रूप में दिखाया गया था। दूसरा यह है कि, हालांकि फॉर्म में विशेष रूप से याचिकाकर्ता को यह खुलासा करने की आवश्यकता थी कि वह विशिस्ट विषयों में उत्तीर्ण हुआ था या अनुत्तीर्ण हुआ था, याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया था।

19 फरवरी 2014 को दिनांकित पात्रता प्रमाण पत्र

9. 19 फरवरी 2014 को, याचिकाकर्ता को एफएमआई विनियमों के संदर्भ में एमसीआई द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें उसे एक विदेशी संस्थान से प्रारंभिक आयुर्विज्ञान अहर्ता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा की गई योग्यता परीक्षा का विवरण पात्रता प्रमाण पत्र में इस प्रकार दर्ज किया गया है:

विषय	**कुल अंक**	**प्राप्त अंक**	**%**	**परिणाम**
अंग्रेज़ी	100	92	92.00	पास
भौतिक विज्ञान	100	40	40.00	पास
रसायन विज्ञान	100	52	52.00	पास
जीव विज्ञान	100	64	64.00	पास
पीसीबी टोटल	300	156	52.00	पास

10. यहाँ पुनः पात्रता प्रमाण-पत्र में याचिकाकर्ता के कक्षा 12$^{वीं}$ की परीक्षा के परिणाम को दर्ज करने के तरीके की दो विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। पहला यह है

कि पात्रता प्रमाण-पत्र में याचिकाकर्ता को भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण बताया गया है, हालांकि उसे केवल 40 अंक प्राप्त हुए थे और वह वास्तव में उस विषय में अनुत्तीर्ण था। दूसरा यह है कि, यद्यपि याचिकाकर्ता ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए अपने आवेदन में, जिस विषय में अंक प्राप्त किए थे, उसके अनुसार अपने अंकों को गड़बड़ कर दिया था, तथापि पात्रता प्रमाण-पत्र में दर्ज अंकों में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विराज कदम ने तर्क दिया कि उनके द्वारा प्रयुक्त सटीक अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए यह एक "अप्रत्यक्ष कृपादान" था– चूंकि इससे यह संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए अपने आवेदन में अपने अंकों में गड़बड़ी की थी लेकिन यह तथ्य कि उक्त गड़बड़ी पात्रता प्रमाण-पत्र के मुख्य भाग में विभिन्न विषयों के लिए निर्धारित अंकों में नहीं दिखाई गई थी यह दर्शाता है कि एमसीआई ने याचिकाकर्ता द्वारा कक्षा 12 में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर नहीं, जैसा कि उसने अपने आवेदन में दर्ज किया था, बल्कि सीबीएसई द्वारा जारी वास्तविक कक्षा 12 एआईएसएससीई प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया।

<u>एमबीबीएस पाठ्यक्रम और उसके उपरांत</u>

11. एमसीआई द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने रूस की यात्रा की और 2012 में एसएसएमयू में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अपना

दाखिला लिया था। उन्होंने जून 2018 में विश्वविद्यालय से अपना एमबीबीएस कोर्स पूरा किया और 30 जून 2018 को एसएसएमयू द्वारा एक पास प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

12. याचिकाकर्ता भारत लौट आया और एफएमजीई में उपस्थित होने की अनुमति के लिए आवेदन किया ताकि वह विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक (एफएमजी) के रूप में भारत में चिकित्सा व्यवसाय कर सके। एनबीईएमएस द्वारा याचिकाकर्ता को एक हॉल टिकट जारी किया गया था जिससे उसे एफएमजीई में उपस्थित होने की अनुमति मिली।

13. याचिकाकर्ता 2020 में अपने चौथे प्रयास में ही एफएमजीई को पास कर सका जिसके बाद एनबीईएमएस ने 1 अक्टूबर 2020 को जाँच परीक्षण पास प्रमाण-पत्र (एसटीपीसी) जारी किया।

14. एसटीपीसी और एसएसएमयू द्वारा जारी किए गए एमबीबीएस के प्रमाण-पत्र के साथ, याचिकाकर्ता ने 10 अप्रैल 2021 को डीएमसी में आवेदन किया कि उसे चिकित्सक डॉक्टर के रूप में पंजीकरण करने की अनंतिम अनुमति दी जाए।

<u>आक्षेपित पत्र</u>

15. क्योंकि आवेदन डी.एम.सी. के पास विचाराधीन था इसलिए याचिकाकर्ता यह दावा करता है कि उसे 26 जुलाई 2021 को एनएमसी द्वारा और इसके बाद 23

अगस्त 2020 को एनबीईएमएस द्वारा जारी किए गए आक्षेपित पत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे वह "स्तब्ध और आश्चर्यचकित" है।

16. ये पत्र निम्नानुसार हैं:-

<u>एनएमसी द्वारा 26 जुलाई 2021 को जारी किया गया आक्षेपित पत्र:</u>

"राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी)

ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. आर.15012/04/2021-पंजी./016505

26.07.2021

सेवा में,

सचिव, डीएमसी,
ग्राउंड फ्लोर, बी विंग
ब्लॉक-1 डीएमआरसी आईटी पार्क,
शास्त्री पार्क नई दिल्ली 110053।

<u>विषयः पात्रता प्रमाण-पत्र विनियमन अधिनियम, 2002 धारा (5) के अनुसार पात्रता प्रमाण-पत्र सं. एमसीआई-201 (ईसी 12-11215)/2014-पात्र./(14-34808) को वापस ले लिया गया।</u>

सर/मैडम।

मुझे आपके पत्र सं. डीएमसी/28/2/2021/296060 दिनांक 11 मई, 2021 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जिसमें श्री नितिन थॉमस से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, भले ही उम्मीदवार भौतिक विज्ञान विषय के थ्योरी भाग में फेल हुआ हो। इस संबंध में, आपको सूचित किया जाता है कि इस आयोग में मामले की जांच की गई है, निम्नलिखित कहा गया है:

(i) कि उम्मीदवार ने अपने आवेदन में भौतिक विज्ञान विषय में खुद को पास घोषित किया है और उसी के आधार पर उसे पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक उम्मीदवार जो "प्रैक्टिकल कार्य से जुड़े विषय" की परीक्षा देता है उसे उस विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुल 33% अंकों के अलावा थ्योरी में 33% अंक और प्रैक्टिकल में 33% अंक प्राप्त करने होते है। तथापि, आगे जांच करने पर यह पाया गया है कि अभ्यर्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा के भौतिक विज्ञान विषय के थ्योरी भाग में अहर्ता/अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है।

(ii) इसके अलावा, स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन अधिनियम, 1997 की धारा 5(1) के अनुसार जो प्रावधान

है:- अहर्ता के आधार पर खंड (1) के तहत अर्हक परीक्षा के आधार पर प्रवेश के मामले में, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी के विषयों में अलग से उत्तीर्ण होना चाहिए और योग्यता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में एक साथ न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। जैसा कि विनियमन 4 के खंड (2) में उल्लिखित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अर्हक परीक्षा में एक साथ प्राप्त अंक उपरोक्त 50% के बजाय 40% होंगे।

इसलिए, वह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी के विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

(iii) इसके अलावा, पात्रता प्रमाण-पत्र विनियमन अधिनियम, 2002 की धारा (5) के अनुसार पात्रता प्रमाण-पत्र यदि पहले ही जारी किया जा चुका है तो रद्द किया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

परिषद उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई जानकारी की शुद्धता की जांच करने और/या उम्मीदवार से इस संबंध में कोई और जानकारी

मांगने के लिए स्वतंत्र होगी और ऐसी जांच के दौरान या किसी भी बाद के चरण में उम्मीदवार द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को गलत या त्रुटिपूर्ण पाए जाने की स्थिति में परिषद पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने से इनकार कर सकती है या यदि पहले से जारी किया गया है तो उसे रद्द कर सकती है और उसे बिना किसी सूचना के भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (4क) में निर्धारित जाँच परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाएगा। इस संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

2. उपरोक्त के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि श्री नितिन थॉमस को पात्रता प्रमाण-पत्र सं. एमसीआई-201(ईसी-12-11215)/2014- पात्रता/(14-34808) दिनांकित 19.02.2014 को रद्द कर दिया गया है और उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने से वंचित किया जाता है।

3. यह अध्यक्ष (ईएमआरबी) की मंजूरी से जारी किया जाता है।

भवदीय,
हस्ताक्षर
(राजीव कुमार)
अवर सचिव

<u>एनबीईएमएस द्वारा जारी 23 अगस्त 2021 का आक्षेपित पत्र:</u>

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्वायत्त निकाय)
संद.सं.एनबीईएमएस/एफएमजीई/51022//दिसम्बर-2020/5552-5553 दिनांकित: 23/08/2021

सेवा में,

श्री नितिन थॉमस,
कैलाश भवन, रामकृष्ण पथ पिरमुहानी,
पटना बिहार-800003

विषयः एफएमजीई जून 2020 सत्र के लिए एफएमजीई पास प्रमाण-पत्र निरस्त करने- के संबंध में

प्रिय उम्मीदवार,

यह 31 अगस्त 2021 को आयुर्विज्ञान मे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अनुक्रमांक सं. 2011114722 के प्रति एफएमजीई जून 2020 सत्र में आपकी उपस्थिति के संदर्भ में है। एफएमजीई स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने पर आपको 18 नवंबर 2021 को ई-मेल के माध्यम से एफएमजीई पास प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2021 के अपने पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि आपको जारी पात्रता प्रमाण-पत्र सं. एमसीआई-201 ((ईसी12-

11215)/2014-पात्रता/(14-34808) दिनांकित 19.02.2014 को रद्द कर दिया गया है और आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने से रोक दिया गया है।

एफएमजीई जून 2020 सत्र के लिए सूचना बुलेटिन के खंड 2.16 के अनुसार, "एफएमजी परीक्षा के किसी भी चरण में अयोग्य पाए गए उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी भी अयोग्य उम्मीदवार के एफएमजी परीक्षा में उपस्थित होने और/ या उत्तीर्ण करने की संभावना नहीं होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार के परिणाम/उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा और/या रद्द माना जाएगा। भले ही परिणाम घोषित कर दिया गया हो या पास प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो। उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि आपकी एफएमजीई जून 2020 सत्र की उम्मीदवारी अब रद्द कर दी गई है। चूंकि आपको इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए आपको जारी किया गया एफएमजीई पास प्रमाण-पत्र सं. एनबीई/डीओईसी/51022/जून2020/2011000711/71 दिनांक 18 नवंबर 2020 रद्द कर दिया गया है।

आपको एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाण पत्र किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद या किसी अन्य संगठन को किसी भी उद्देश्य के लिए प्रस्तुत न करें। इसके अतिरिक्त, इस

मामले की सूचना सभी राज्य आयुवज्ञान परिषदों को भी दी गई है।

भवदीय,
हस्ताक्षर
रश्मि मुंजाल
सहायक निदेशक (एनएम)
परीक्षा विभाग

प्रतिलिपि:

एफएमजीई पास प्रमाण-पत्र **रद्द** किए जाने के मद्देनजर उचित कार्रवाई करने के लिए संलग्न सूची के अनुसार सभी राज्य आयुर्विज्ञान परिषद संलग्न हैं|

17. उक्त पत्र से व्यथित, याचिकाकर्ता, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, ने एनएमसी को प्रत्यर्थी 1 और एनबीईएमएस को प्रत्यर्थी 2 के रूप में पेश करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की।

प्रतिद्वंद्वी प्रतिवाद

18. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विराज कदम, एनएमसी के विद्वान अधिवक्ता श्री टी. सिंहदेव और एनबीईएमएस के विद्वान अधिवक्ता श्री कीर्तिमान सिंह को विस्तार से सुना है। याचिकाकर्ता और एनबीईएमएस द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ पहले ही दायर की जा चुकी हैं।

<u>श्री विराज शंकर कदम की प्रस्तुतियाँ:</u>

19. याचिकाकर्ता के लिए श्री विराज शंकर कदम की प्रस्तुतियाँ इस प्रकार प्रगणित की जा सकती हैं:

(i) आक्षेपित निर्णय के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को उसके जीवन में 14 साल पीछे ढकेल दिया गया जिससे रूस में उसकी शिक्षा की पूरी अवधि, उसे जारी किए गए एमबीबीएस प्रमाण-पत्र, एफएमजीई जाँच परीक्षा जो उसने दिया था और अपने चौथे प्रयास में एफएमजीई में उसकी अंतिम सफलता को रद्द कर दिया गया था। यह कानून में पूरी तरह से अकल्पनीय था और इसके परिणामस्वरूप अपूरणीय पूर्वाग्रह हुआ, जिसकी भरपाई धन या नुकसानी से नहीं की जा सकती थी।

(ii) हालाँकि याचिकाकर्ता भौतिक विज्ञान के अपने थ्योरी परीक्षा में फेल हो गया था लेकिन सीबीएसई द्वारा जारी एआईएसएससीई प्रमाण-पत्र के अनुसार पास था।

(iii) याचिकाकर्ता के आवेदन के बाद उसे पात्रता प्रमाण-पत्र देने से पूर्व एमसीआई ने दो साल का समय लिया था। इसलिए, स्पष्ट रूप से, प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व एमसीआई ने उचित सावधानी बरती थी। इस संदर्भ में श्री कदम एफएमआई विनियमों के विनियम 5 और 9 पर इस प्रकार निर्भर करते हैं:

5. परिषद उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई जानकारी की शुद्धता की जांच करने और/या उम्मीदवार से इस संबंध में कोई और जानकारी मांगने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसी जांच के दौरान या किसी भी बाद के चरण में उम्मीदवार द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को गलत या त्रुटिपूर्ण पाए जाने की स्थिति में, परिषद पात्रता प्रमाण- पत्र जारी करने से इनकार कर सकती है या यदि पहले से जारी किया गया है तो उसे रद्द कर सकती है और उसे बिना किसी सूचना के भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (4क) में निर्धारित जाँच परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाएगा। इस संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

9. सत्यापन के बाद, आवश्यकतानुसार, यदि उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए पाया जाता है तो परिषद उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में एक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करेगी जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि वह प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के लिए भारत से बाहर किसी चिकित्सा संस्थान में शामिल होने के लिए पात्र है। प्रमाण-पत्र में यह उल्लेख होगा कि विदेशी प्रारंभिक आयुर्विज्ञान अर्हता प्राप्त करने के बाद लौटने पर, उम्मीदवार को स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जाँच परीक्षा से गुजरना होगा और

इस परीक्षा को पास करने से वह केवल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्वारा अनंतिम/स्थायी पंजीकरण का हकदार होगा।

(vi) हालांकि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में, अनजाने में बारहवीं कक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में उन विषयों की तुलना में गड़बड़ कर दी थी जिनमें उसने उक्त अंक प्राप्त किए थे, अनजाने में हुई गलती से अंततः कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एमसीआई द्वारा जारी 19 फरवरी 2014 के पात्रता प्रमाण-पत्र में, सीबीएसई द्वारा जारी उसकी एआईएसएससीई मार्क-शीट के अनुसार विषयों के लिए अंक आवंटित किए गए थे। दूसरे शब्दों में, एमसीआई ने याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र पर दिखाए गए अंकों के आधार पर नहीं, बल्कि सीबीएसई द्वारा जारी बारहवीं कक्षा की वास्तविक एआईएसएससीई अंक-पत्र के आधार पर कार्रवाई की थी।

(v) एक बार जब एमसीआई ने सीबीएसई द्वारा जारी एआईएसएससीई कक्षा बारहवीं की मूल अंक-पत्रक को ध्यान में रखा और याचिकाकर्ता को सभी अपेक्षित कागजात में उत्तीर्ण माना और इसलिए, पात्रता प्रमाण-पत्र अनुदान करने का हकदार माना तो एमसीआई कई वर्षों के बाद अपने निर्णय पर

फिर से विचार नहीं कर सका और याचिकाकर्ता को हकदार नहीं ठहरा सका।

(vi) इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता साम्यिक विबंधन के सिद्धांत का भी आह्वान करता है क्योंकि एमसीआई द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता ने रूस में छह साल तक चिकित्सा का अध्ययन किया और एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। इसलिए याचिकाकर्ता ने एमसीआई द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र के आधार पर अपना रुख बदल दिया। इसलिए, एमसीआई को साम्यिक विबंधन के सिद्धांत पर इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था जिसके लिए श्री कदम ने ***मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमि. बनाम यूपी राज्य***[1] मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 8 से 10, 13 से 16, 19, 22, 24 और 25 को अवलंब किया।

(vii) याचिकाकर्ता को किसी भी स्तर पर गलत नहीं कहा जा सकता है। पात्रता प्रमाण-पत्र देने के लिए अपने आवेदन के साथ याचिकाकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और पूरी जानकारी प्रदान की थी। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी बारहवीं कक्षा की मार्कशीट सहित किसी भी आवश्यक दस्तावेज को छिपाने का कोई आरोप नहीं था।

(viii) याचिकाकर्ता ने एफएमजी में भागीदारी के लिए आवेदन करते समय सभी चार अवसरों पर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। दूसरे शब्दों में, एमसीआई ने दस्तावेजों को न केवल उस चरण में देखा था जब याचिकाकर्ता ने विदेश में व्यवसाय के लिए पात्रता प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन किया था बल्कि प्रत्येक उन अवसरों पर भी देखा जब याचिकाकर्ता ने एफएमजीई से गुजरने की अनुमति के लिए आवेदन किया था।

(ix) यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि, शुरू में, दिनांक 19 फरवरी 2014 को पात्रता प्रमाण-पत्र गलत तरीके से जारी किया गया था, फिर भी, यह जारी किया गया था कि इसे वापिस नहीं लिया जा सकता था।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री कदम ने **राजेंद्र प्रसाद माथुर बनाम कर्नाटक विश्वविद्यालय**[2]**, ए. सुधा बनाम मैसूर विश्वविद्यालय**[3]**, अशोक चंद सिंघवी बनाम जोधपुर विश्वविद्यालय**[4] **और चौधरी नवीन हेमाभाई बनाम गुजरात राज्य**[5] में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर किया है।

<u>श्री सिंहदेव के निवेदन प्रतिक्रिया के रूप में</u>

20. श्री सिंहदेव प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता राहत पाने का हकदार नहीं है और इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रतिविरोध प्रस्तुत किए गएः

(i) याचिकाकर्ता 19 फरवरी 2014 को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी होने से पूर्व ही रूस के लिए रवाना हो गया था। यह अपने आप में अनियमित था क्योंकि यह माना जाता है कि विदेश में पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना एक पूर्व शर्त थी। इसलिए, याचिकाकर्ता इस आधार पर समानता का अभिवचन करने के लिए स्वतंत्र नहीं था कि उसने रूस में एमबीबीएस पाठ्यक्रम किया था।

(ii) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने की पात्रता है- स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 (इसके बाद जी.एम.ई. विनियम) द्वारा समावेश किया गया है। जीएमई विनियमों के विनियम 5(5)(i) इस प्रकार है:-

(5) एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चयन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:-

i) योग्यता के आधार पर खंड (1) के तहत अहर्ता परीक्षा के आधार पर दाखिले के मामले में, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी के प्रत्येक विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए और विनियम[4] के खंड (2) में उल्लिखित अहर्ता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी में एक साथ लिए गए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में, अहर्ता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन

विज्ञान और जीव विज्ञान में प्राप्त अंक उपरोक्त के अनुसार 50% के बजाय 40% होनी चाहिए।

इसलिए, एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने के पात्रता के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी को प्रत्येक रूप से पास करना एक पूर्वापेक्षा है। इसके अलावा, बारहवीं कक्षा की परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक भी आवश्यकता है। जीएमई विनियमों के विनियमन 5(5)(i) में अंतर्विष्ट एमबीबीएस पाठ्यक्रम करने के लिए पात्रता मानदंड को एफएमआई विनियमों के विनियमन 8 के संदर्भ द्वारा शामिल किया गया था, जो इस प्रकार है:-

> 8. परिषद पात्रता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पर विचार करेगी और परिषद के विनियमों के अनुसार निम्नलिखित विवरणों को सत्यापित करेगी-
>
> (i) क्या उम्मीदवार परिषद द्वारा निर्धारित आयु मानदंड को पूरा करता है?
>
> (ii) क्या उम्मीदवार भारत में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है,
>
> अर्थात, यदि उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से संबंधित है तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी में शिथिल मानदंड के साथ न्यूनतम योग्यता अंक मानदंड में शामिल हैं?
>
> (iii) यदि उम्मीदवार एससी/एसटी/ओबीसी से संबंधित है, तो क्या उसने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है?

याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में प्रत्येक विषय के रूप से उत्तीर्ण होने की आवश्यकता के लिए समस्या में था, क्योंकि वह बारहवीं कक्षा में अपने भौतिक विज्ञान के परीक्षा में असफल रहा था|

(iii) यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी जिसके आधार पर प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, अमान्य या गलत था तो एफएमआई विनियमों का विनियम 56 एनएमसी को पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के बाद किसी भी स्तर पर, उसे रद्द करने का अधिकार देता है|

(iv) स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमों के विनियम 4(2)[7] में विदेश से प्राथमिक चिकित्सा अर्हता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने से तब तक प्रतिबंधित किया गया है जब तक कि उम्मीदवार ने एफएमआई विनियमों के अनुसार एमसीआई से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो। चूंकि याचिकाकर्ता पात्रता प्रमाण-पत्र का हकदार नहीं था इसलिए वह स्क्रीनिंग विनियम 2002 के विनियम 4(2) के आधार पर एफएमजीई में उपस्थित होने का हकदार नहीं था। इस संदर्भ में, श्री सिंहदेव ने ***रोहिणीश पाठक बनाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्***[8] में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय का हवाला दिया है जिसके

खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जिसे 15 नवंबर 2021 को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

(v) याचिकाकर्ता को बारहवीं कक्षा में उसके भौतिक विज्ञान की परीक्षा के लिए समग्र रूप से ग्रेड ई दिया गया था। सीबीएसई की परीक्षा और उत्तीर्ण मानदंड की योजना के उपबंध 38 (v) में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि ग्रेड 'ई' प्राप्त करने वाला उम्मीदवार उस परीक्षा में फेल हो गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता यह प्रतिवाद देने की कोशिश नहीं कर सका कि उसने प्रैक्टिकल में भी भौतिक विज्ञान की परीक्षा पास की थी|

(vi) पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन के साथ, याचिकाकर्ता ने सदस्यता ली और निम्नलिखित घोषणा पर हस्ताक्षर किएः

घोषणा

> मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में मेरे द्वारा की गई प्रविष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं स्वीकारता हूं कि मैं एमसीआई, नई दिल्ली से किसी भी सूचना के बिना मेरे द्वारा प्रस्तुत किसी भी गलत जानकारी या दस्तावेज के लिए कानून के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूं।
>
> मैं यह भी समझता हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता की जांच करने और/या मुझसे इस संबंध में कोई

और जानकारी मांगने के लिए स्वतंत्र होगा और मेरे द्वारा दी गई किसी भी जानकारी के गलत या झूठा पाए जाने की स्थिति में ऐसी जांच के दौरान *या किसी भी बाद के चरण में परिषद पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने से इनकार कर सकती है या यदि पहले से जारी किया गया है तो इसे रद्द कर सकती है और मैं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (4क) में निर्धारित स्क्रीनिंग टेस्ट और एमसीआई, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए किसी भी अन्य नियम और विनियमन में बिना किसी सूचना के उपस्थित होने से वंचित हो जाऊंगा।*

मैं भली भांति जानता हूँ कि विदेश में मान्यता प्राप्त प्रारंभिक अयूर्विज्ञान अर्हता प्राप्त करने के बाद और ऊपर दिए गए सत्यापन के अनुसार मुझे भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करनी होगी जिसे विदेशी चिकित्सा संस्थान विनियम, 2002 में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्रता आवश्यकता के साथ पढ़ा जाना चाहिए तथा जाँच परीक्षण विनियम, 2002 का अनुपालन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा अनंतिम/स्थायी पंजीकरण प्रदान करने से पहले किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षर

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

नाम -नितिन थॉमस

स्थानः पटना

तारीखः 1/8/2012

(जोर दिया गया)

vii) 19 फरवरी 2014 के पात्रता प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित विशिष्ट अस्वीकरण भी शामिल था:

> यह प्रमाणित करने हेतु है कि उम्मीदवार श्री/सुश्री नितिन थॉमस, पुत्र/पुत्री नेदुमथरा थॉमस द्वारा प्रस्तुत विवरण/दस्तावेजों और घोषणा के अनुसार वह स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002 के अनुसार विदेश में स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान में भारत में एमबीबीएस के समकक्ष विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 2002 में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता आवश्यकता के अनुसार '*प्रारंभिक अयूर्विज्ञान अर्हता*' की ओर ले जाने वाले चिकित्सा पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने/स्नातक करने के लिए एक विदेशी चिकित्सा संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यह प्रमाण-पत्र निम्नलिखित के अधीन है (i) एमसीआई विनियमन स्नातक चिकित्सा शिक्षा, 1997 स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002 के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करना है, जैसा कि 2009 में संशोधित किया गया। *(ii) ऐसे विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान और उस विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना जिसके साथ ऐसे संस्थान संबद्ध है (iii) उसके पास वैध पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेज होने चाहिए।"*

(xii) पात्रता प्रमाण-पत्र के मुख्य भाग पर निम्नलिखित नोट भी अंकित है:

> 1. यह पात्रता प्रमाण-पत्र विशेष रूप से आवेदक द्वारा उसके आवेदन पत्र के साथ दी गई जानकारी/दस्तावेजों और घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए लंबित है।"

21. इन परिस्थितियों में, श्री सिंहदेव का कहना है कि याचिकाकर्ता अपने समर्थन में **निधि कैम बनाम मध्य प्रदेश राज्य[9] में सर्वोच्च न्यायालय** के फैसले के पैरा 1, 71, 72, 92, 94 और 97, **सीएमडी, एफसीआई बनाम जगदीश बलराम बहिरा[10]** में **उच्चतम न्यायालय** के निर्णय के अनुच्छेद 3, 48, 66 और 68 और **एमसीआई बनाम रूस कल्याण संघ के भारतीय डॉक्टर[11]** के निर्णय के अनुच्छेद 6 के मामले में राहत पाने का पूरी तरह से हकदार नहीं है|

22. श्री सिंहदेव ने उन प्राधिकारियों को अलग करने की भी मांग की, जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है।

<u>प्रत्युत्तर में श्री कदम की प्रस्तुतियाँ|</u>

23. श्री विराज कदम ने अपने प्रत्युत्तर में उन निर्णयों को अलग करने की मांग की जिन पर श्री सिंहदेव ने भरोसा किया था। वह प्रस्तुत करते हैं कि ***रोहनीश पाठक*** एक ऐसा मामला है जिसमें पात्रता प्रमाण-पत्र देने के अनुरोध को तीन बार

खारिज कर दिया गया था। अन्य निर्णय या तो प्रकट धोखाधड़ी से संबंधित थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला या केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया से विचलन।

24. समापन उपलक्ष के रूप में, श्री कदम प्रस्तुत करते हैं कि 2014 में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के चरण में याचिकाकर्ता के अविवेक, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था और एफएमजीई जाँच परिक्षण भी पास किया था। इसलिए, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए उनकी योग्यता या क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

विश्लेषण

25. याचिकाकर्ता को कोई राहत देना संभव नहीं है।

<u>याचिकाकर्ता जीएमई विनियमों के विनियमन 5(5)(i) के साथ पठित एफएमआई विनियमों के विनियमन 8 के तहत पात्रता प्रमाण-पत्र का हकदार नहीं है|</u>

26. एफएमआई विनियमों के विनियम 8 में विशेष रूप से यह अपेक्षा की गई है कि विदेश में एमबीबीएस पाठ्यक्रम करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को एफएमआई विनियमों में यथा निर्धारित भारत में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है। जीएमई विनियमों के विनियमन 5(5)() के लिए उम्मीदवार को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और

अंग्रेजी में प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता होती है इसके अलावा अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होते हैं। अर्हक परीक्षा, बेशक, उम्मीदवार द्वारा दी गई बारहवीं कक्षा की परीक्षा है।

27. अपने कक्षा XII भौतिक विज्ञान की परीक्षा में थ्योरी पेपर में व्यक्तिगत रूप से असफल होने के अलावा, याचिकाकर्ता को समग्र रूप से ई ग्रेड दिया गया था। परीक्षा और पास मानदंड की योजना में खंड 38(V) के अनुसार ग्रेड ई, यह दर्शाता है कि उम्मीदवार पेपर में असफल रहा है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में, उसके भौतिक विज्ञान के परीक्षा को स्पष्ट रूप से विफल कर दिया गया था और इसलिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं था, या, परिणामस्वरूप, एक विदेशी संस्थान से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

<u>आवेदन पत्र में गलत विवरण और छिपाना</u>

28. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने एमबीबीएस करने के लिए यात्रा करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा दायर आवेदन में गलत कथन का सहारा लिया है। याचिकाकर्ता द्वारा अपने रसायन विज्ञान के पेपर में प्राप्त अंकों को भौतिक विज्ञान परीक्षा में प्राप्त अंकों के रूप में दिखाया गया था, जीव विज्ञान में

प्राप्त अंकों को रसायन विज्ञान में प्राप्त अंकों के रूप में दिखाया गया था और भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंकों को जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों के रूप में दिखाया गया था|

29. इसके अलावा, हालांकि प्रवेश फॉर्म में विशेष रूप से याचिकाकर्ता को यह इंगित करने की आवश्यकता थी कि वह परीक्षा में पास हुआ था या फेल, जो की नहीं किया गया था। नतीजतन, क्योंकि अलग-अलग विषयों के अंकों को गड़बड़ कर दिया गया था और इस बात का कोई संकेत नहीं था हालांकि आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से आवश्यक था कि याचिकाकर्ता वास्तव में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा में प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हुआ था। यदि याचिकाकर्ता ने उक्त विवरण दर्ज किया होता, तो यह स्पष्ट हो जाता कि याचिकाकर्ता भौतिक विज्ञान में असफल रहा था। इससे भी बदतर यह होता कि यह स्पष्ट हो जाता कि याचिकाकर्ता ने अपने भौतिक विज्ञान के परीक्षा में गलत अंक दर्ज किए थे।

30. न्यायालय यह नहीं मान सकता कि ये सभी लोप और अनियमितताएं निरपराध थीं।

<u>पुनः तर्क यह है कि आवेदन पत्र की त्रुटियां पात्रता प्रमाणपत्र में परिलक्षित नहीं होती हैं|</u>

31. कुछ हद तक आश्चर्यजनक रूप से, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कदम ने यह तर्क देने की मांग की कि हालांकि याचिकाकर्ता अपने आवेदन पत्र को भरने में लापरवाही कर सकता है, आवेदन पत्र में निहित गलत विवरण अंततः एमसीआई द्वारा जारी 19 फरवरी 2014 के पात्रता प्रमाण-पत्र को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा अंग्रेजी में बारहवीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, उक्त पात्रता प्रमाण पत्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को सही ढंग से दर्ज किया गया था। श्री कदम के अनुसार, यह इंगित किया जाता है कि एमसीआई ने पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करते समय सीबीएसई द्वारा जारी वास्तविक बारहवीं कक्षा एआईएसएससीई प्रमाण-पत्र पर ध्यान दिया, न कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किए गए गलत विवरण पर।

32. प्रस्तुतिकरण वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह मुश्किल झूठ बोल जा सकता है कि याचिकाकर्ता का तर्क देना, गलत कथन का सहारा लेना और उसके आवेदन पत्र में दमन कि न्यायालय को इस पर आंखे खोलनी चाहिए, क्योंकि गलत बयानबाजी और जानकारी को दबाने से अंततः एमसीआई द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

<u>आवेदन पत्र के साथ दाखिल की गई घोषणा</u>

33. वास्तव में, याचिकाकर्ता ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन के साथ एक घोषणा दायर की जिसमे प्रमाण-पत्र में दी गई जानकारी को गलत पाए जाने पर एमसीआई को बाद के चरण में जारी किए गए पात्रता प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार दिया था। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में झूठी घोषणा करने के परिणामों के बारे में पूरी जानकारी होते हुए भी उपरोक्त में गलत विवरण दर्ज किए। इसलिए, वह अब अपने पक्ष में साम्य का अभिवचन नहीं कर सकता ।

<u>एफ.एम.आई. विनियमों का विनियम 5</u>

34. यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी गलत या झूठी है, तो एमसीआई/एनएमसी को किसी भी बाद के चरण में पात्रता प्रमाण पत्र को रद्द करने का अधिकार भी एफएमआई विनियमों के विनियमन 5 द्वारा संरक्षित है। याचिकाकर्ता द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिए गए विवरण स्पष्ट रूप से झूठे थे। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वे अलग-अलग विषयों में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हुए हैं या नहीं, जिससे दमन का रास्ता अपनाया गया जिसमें, यदि यह घोषित किया गया होता, तो निश्चित रूप से उसे पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया होता। इसलिए, पात्रता प्रमाणपत्र को उन्होंने छिपाकर

और गलत बयान देकर प्राप्त किया था, और उन्हें इसका लाभ लेने की अनुमति देने में कोई न्याय नहीं किया जा सकता।

<u>स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमों का नियम 4(2)- एफएमजीई में उपस्थित होने में असमर्थता</u>

35. स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमों का नियम 4(2) स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को एफएमजीई में शामिल होने से बाधित करता है, जब तक कि उसने एफएमआई विनियमों के अनुसार एमसीआई से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो। "जैसा" कि अभिव्यक्ति को पी. रामनाथन अय्यर के लॉ लेक्सिकन (छठे संस्करण) में के अनुसार; की शर्तों के अनुसार; के अनुसार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, एफएमआई विनियमों की शर्तों के अनुसार पात्रता प्रमाणपत्र को एफएमआई विनियमों के अनुसार प्राप्त माना जाना अपरिहार्य अनिवार्य शर्त है।

36. याचिकाकर्ता का पात्रता प्रमाण-पत्र एफएमआई विनियमों का उल्लंघन है और नियम 5 के संदर्भ में रद्द किए जाने योग्य है। परिणाम स्वरुप, याचिकाकर्ता, इस कारण से भी, एफएमजीई शुरू करने के लिए पात्र नहीं था|

<u>पात्रता प्रमाण-पत्र में अस्वीकरण</u>

37. इसके अलावा, 19 फरवरी 2014 के पात्रता प्रमाणपत्र में एक विशिष्ट अस्वीकरण भी शामिल था जो इसे याचिकाकर्ता द्वारा जीएमई विनियम और जाँच

परिक्षण विनियम 2002 के अनुसार पात्रता मानदंड की पूर्ति के अधीन रखता है। याचिकाकर्ता स्वीकार्य रूप से अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अनुशीलन के लिए विदेश यात्रा के मानदंडों को पूरा नहीं करता है जैसा कि जीएमई विनियमों के विनियम 5(5)(i) द्वारा परिकल्पित है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के पात्रता प्रमाण पत्र को रद्द करना भी अस्वीकरण के संदर्भ में था जो पात्रता प्रमाण पत्र के मुख्य भाग में ही दर्ज किया गया था।

<u>इस न्यायालय से दमन और छिपाना</u>

38. याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष न के बराबर सच्चाई पेश की है। याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता की बारहवीं कक्षा की मार्कशीट के पीछे सीबीएसई द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देश को अभिलेख में नहीं रखा है जिसका अर्थ है कि ग्रेड ई से संकेत मिलता है कि उम्मीदवार पेपर में फेल हो गया था। दूसरी ओर, उन्होंने रिट याचिका में यह दर्शाने की मांग की है कि वह सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे और केवल भौतिक विज्ञान के थ्योरी परीक्षा में विफल हुए थे।

39. न ही याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 1 अगस्त 2012 को अभिलेख पर रखने की भी अनुमति दी, जो उसने पात्रता प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए आवेदन करते समय भरा था, प्रथमदृष्टया क्योंकि फॉर्म से पता चलता कि इसमें याचिकाकर्ता द्वारा बड़े गलत बयान और दमन किए गए थे।

40. इसलिए, स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता ने निर्दोष के रूप में इस न्यायालय को अनुरोध नहीं किया है। उन्होंने अपने स्वयं के कृत्यों द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय की न्यायसंगत पहुंच से खुद को बाहर रखा है।

41. ***मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स*** में निर्णय एक कर मामले में दिया गया था और अपीलार्थी को उक्त छूट का हकदार होने के बावजूद, *वनस्पति* के विक्रय के लिए अपीलकर्ता को विक्रय कर से छूट देने से इनकार करने के प्रति सरकार के प्रति एक वचन विबंधन के सिद्धांत से निपटाया गया था। स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है अन्य मामले ऐसे उदाहरणों को कवर नहीं करते हैं जिनमें याचिकाकर्ता उन लाभों को प्राप्त करते समय गलत बयानी और दमन का सहारा लेता है जिन्हें वह संरक्षित करना चाहता है, ऐसे मामले तो बहुत कम हैं जिनमें याचिकाकर्ता ने न्यायालय से भी छुपाया है।

निष्कर्ष

42. उपरोक्त कारण से, वर्तमान याचिका पूरी तरह से गुणों से रहित। इसे तदनुसार, बिना किसी जुर्माने के आदेश के खारिज कर दिया जाता है|

न्या. सी. हरि शंकर

13 फरवरी, 2024

आरबी/डीएसएन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*